

**Explanation Unit-V**

1. (B) Arjun Singh was an Indian politician from the Indian National Congress, who served twice as the Chief Minister of Madhya Pradesh in the 1980s. He also served twice as the Union Minister of Human Resource Development, in the Manmohan Singh and P. V. Narasimha Rao ministries.
2. (C) For any meeting of the Gram one-tenth of the total number of members of the Gram Sabha shall be for the quorum. The meeting of the Gram Sabha shall be convened by the Secretary of the Gram Panchayat constituted for the Gram Sabha are in the prescribed manner.
3. (A) In order to ensure reasonable level of utilization of core functionaries, it is recommended that a Gram Panchayat may be constituted with a minimum population of 5000.
4. (D) Eleventh schedule of Indian Constitution contains the following functional items placed within the purview of the Panchyats:
  1. Agriculture including agricultural expansion.
  2. Land improvement, implementation of land reforms, land consolidation and soil conservation.
  3. Animal Husbandry, Dairying and poultry.
  4. Fisheries Industry.
  5. Minor irrigation, water management and watershed development.
  6. Social forestry and farm forestry.
  7. Small scale industries in which food processing industry is involved.
  8. Minor forest produce.
  9. Safe water for drinking.
  10. Khadi, village and cottage industries.
  11. Rural housing.
  12. Fuel and fodder.
  13. Rural electrification, including distribution of electricity.

1. अर्जुन सिंह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक भारतीय राजनेता थे, जिन्होंने 1980 के दशक में दो बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। उन्होंने मनमोहन सिंह और पी.वी. नरसिम्हा राव मंत्रालयों में दो बार केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री के रूप में भी कार्य किया।
2. ग्राम की किसी भी बैठक के लिए ग्राम सभा के सदस्यों की कुल संख्या का दसवाँ भाग गणपूर्ति के लिए होगा। ग्राम सभा की बैठक ग्राम सभा के लिए गठित ग्राम पंचायत के सचिव द्वारा निर्धारित तरीके से बुलायी जायेगी।
3. मुख्य पदाधिकारियों के उपयोग का उचित स्तर सुनिश्चित करने के लिए, यह अनुशंसा की जाती है कि कम से कम 5000 की आबादी के साथ एक ग्राम पंचायत का गठन किया जाए।
4. भारतीय संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में पंचायतों के दायरे में रखे गए निम्नलिखित कार्यात्मक आइटम शामिल हैं:
  1. कृषि विस्तार सहित कृषि
  2. भूमि सुधार, भूमि सुधारों का कार्यान्वयन, भूमि चकबंदी और मृदा संरक्षण।
  3. पशुपालन, डेयरी और मुर्गी पालन
  4. मत्स्य उद्योग
  5. लघु सिंचाई, जल प्रबंधन और वाटरशेड विकास
  6. सामाजिक वानिकी और कृषि वानिकी
  7. लघु उद्योग जिनमें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग शामिल है
  8. लघु वनोपज
  9. पीने के लिए सुरक्षित पानी
  10. खादी, ग्राम एवं कुटीर उद्योग
  11. ग्रामीण आवास
  12. ईंधन और चारा
  13. बिजली के वितरण सहित ग्रामीण विद्युतीकरण

14. Road, culverts, bridges, ferries, waterways and other means of communication.
15. Education including primary and secondary schools.
16. Non-conventional sources of energy.
17. Technical training and vocational education.
18. Adult and non-formal education.
19. Public distribution system.
20. Maintenance of community assets.
21. Welfare of the weaker sections of the in particular of the schedule caste and schedule tribes.
22. Social welfare, including welfare of the handicapped and mentally retarded.
23. Family welfare.
24. Women and child development.
25. Markets and Fairs.
26. Health and sanitation including hospitals, primary health centres and dispensaries.
27. Cultural activities.
28. Libraries.
29. Poverty Alleviation Programmes.

It is expected that the subjects covered under the eleventh schedule of the indian constitution are made to ensure the development of the rural India.

5. (C) The Constitution (112th Amendment) Bill 2009 to provide for 50% reservation of women in Urban Local Bodies was introduced in Lok Sabha on 24.11. 2009
6. (A) The present house, the fifteenth Vidhan Sabha, was constituted in December 2018. The present building was designed by Charles Correa in 1967, and it was the recipient of the Aga Khan Award for Architecture in 1998.
7. (B) It was established as the Nagpur High Court on 2 January 1936 by Letters Patent dated 2 January 1936, issued under Section 108 the Government of India Act, 1935.

14. सड़क, पुलिया, पुल, घाट, जलमार्ग और संचार के अन्य साधन
  15. प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों सहित शिक्षा
  16. ऊर्जा के गैर-पारंपरिक स्रोत
  17. तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा
  18. वयस्क और अनौपचारिक शिक्षा
  19. सार्वजनिक वितरण प्रणाली
  20. सामुदायिक संपत्ति का रखरखाव
  21. विशेष रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कमजोर वर्गों का कल्याण
  22. विकलांग और मानसिक रूप से मंद लोगों के कल्याण सहित सामाजिक कल्याण
  23. परिवार कल्याण
  24. महिला एवं बाल विकास
  25. बाजार और मेले
  26. अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और औषधालयों सहित स्वास्थ्य और स्वच्छता
  27. सांस्कृतिक गतिविधियां
  28. पुस्तकालय
  29. गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम
- यह उम्मीद की जाती है कि भारतीय संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची के अंतर्गत आने वाले विषयों को ग्रामीण भारत के विकास को सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है।
5. शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान (112वां संशोधन) विधेयक 2009 24.11.2011 को लोकसभा में पेश किया गया था। 2009
  6. वर्तमान सदन, पंद्रहवीं विधानसभा, का गठन दिसंबर 2018 में किया गया था। वर्तमान भवन को 1967 में चार्ल्स कोरिया द्वारा डिजाइन किया गया था, और यह 1998 में वास्तुकला के लिए आगा खान पुरस्कार प्राप्तकर्ता था।
  7. भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 108 के तहत जारी किए गए पत्र पेटेंट दिनांक 2 जनवरी 1936 द्वारा इसे 2 जनवरी 1936 को नागपुर उच्च न्यायालय के रूप में स्थापित किया गया था।

8. (c)
9. (c) An official of the state government will function as a Chief Executive Officer of Janpad Panchayat. The chief executive officer of Janpad Panchayat is appointed for the speedy execution of all developments and work associated with the Janpad Panchayat.
10. (b) The division was inaugurated on 14 June 2008. It comprises Shahdol, Umaria, Anuppur. The total area of this administrative division is 13,920 km<sup>2</sup>
11. (c) Madhya Pradesh has become the first state to enforce "Right to Recall" in local bodies. The public has given "Right to Recall". Pallavalka Patel in Anuppur tehsil of Shahdol district was sacked with this right for the first time.
12. (c) The National Law Institute University, Bhopal (NLIU), was established by the Rashtriya Vidhi Sansthan Vishwavidyalaya Adhiniyam, by an Act No. 41 of 1997 enacted by the Madhya Pradesh State Legislature.
13. (a) The law requires that at least four meetings of the Gram Sabha be held every year, in the months of January, April, July and October.
14. (c) Corporate tax
15. (b) 2014
16. (b) Tribal Research and Development Institute is situated in Bhopal. Tribal Research and Development Institute is an organization of the Government of Madhya Pradesh. It is under the administrative control of the Tribal Welfare Department of the State Government.
17. (a) However, the training so imparted was never considered to be satisfactory and there was a crying need for a formal, institutionalized set up to educate, train and groom members of District Judiciary in such a manner as to equip them with requisite knowledge and skills. It was also
8. (सी)
9. राज्य सरकार का एक अधिकारी जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के रूप में कार्य करेगा। जनपद पंचायत से जुड़े समस्त विकास कार्यों एवं कार्यों के शीघ्र निष्पादन हेतु जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी की नियुक्ति की जाती है।
10. मंडल का उद्घाटन 14 जून 2008 को हुआ था। इसमें शहडोल, उमरिया, अनूपपुर शामिल हैं। इस प्रशासनिक प्रभाग का कुल क्षेत्रफल 13,920 वर्ग किमी . है
11. मध्य प्रदेश स्थानीय निकायों में :राइट टू रि कॉल: लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। जनता ने :राइट टू रि कॉल: दिया है। शहडोल जिले की अनूपपुर तहसील के पल्लवल्का पटेल को पहली बार इस अधिकार से बर्खास्त किया गया।
12. राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय, भोपाल (एनएलआईयू), की स्थापना राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय अधिनियम द्वारा, मध्य प्रदेश राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित 1997 के अधिनियम संख्या 41 द्वारा की गई थी।
13. कानून की आवश्यकता है कि ग्राम सभा की कम से कम चार बैठकें हर साल जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के महीनों में आयोजित की जाएं।
14. कॉर्पोरेट टैक्स
15. 2014
16. आदिवासी अनुसंधान एवं विकास संस्थान भोपाल में स्थित है। जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्थान मध्य प्रदेश सरकार का एक संगठन है। यह राज्य सरकार के आदिम जाति कल्याण विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में है।
17. मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय में जिला न्यायपालिका के सदस्यों को न्यायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए कोई संस्थागत सुविधा नहीं थी। उनके चयन के बाद सिविल जजों और अतिरिक्त जिला जजों को सीधे जिला मुख्यालय में तैनात किया जाता था, जहां उच्चाधिकारियों द्वारा जारी योजना के अनुसार उन्हें जिला जज के पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन में वहां तैनात वरिष्ठ न्यायाधीशों द्वारा व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाता था. कोर्ट। हालांकि, इस प्रकार दिया गया प्रशिक्षण कभी भी संतोषजनक नहीं माना गया

felt necessary that ethical values should be inculcated in Judges of Subordinate Courts from the day one. Thus, the Institute aims at equipping the members of District Judiciary with up to date knowledge of laws and also inculcating and developing in them the qualities of a good Judge so that they can face the challenges of day-to-day judicial work. It was felt that such a conditioning would optimize the inherent qualities of a individual Judge, so that he is in a position to play his designated role effectively and efficiently in the justice delivery system.

**18.(d) Secretary of the Village**

Panchayat convenes the meetings of Gram Sabha. The panchayat is chaired by the president of the village, known as a Sarpanch.

**19.(b) Basant Pratap singh**

**20.(b) Hidayatullah** was the 11th Chief Justice of India from 25 February 1968 to 16 December 1970, and the sixth Vice President of India from 31 August 1979 to 30 August 1984. He was the Acting President of India from 20 July 1969 to 24 August 1969 and from 6 October 1982 to 31 October 1982.

**21.(c) The State Planning Board** was constituted through General Administration Department's resolution dated 24.10. 1972. The Chief Minister is the Chairman of the State Planning Board.

**22. (c) Rs 2,581 crore** has been allocated to Atal Grah Jyoti Yojana. Rs 4,592 crore has been allocated to the Atal Krishi Jyoti Yojana. Rs 3,200 crore has been allocated to the Mukhya Mantri Kisan Kalyan Yojana.

**23.(b) 5<sup>th</sup> five year plan.**

**24.(c) Fiscal deficit for 2021-22** is estimated to be Rs 50,598 crore (4.47% of GSDP). In 2020-21, fiscal deficit is estimated to increase to 5.66% of GSDP

और जिला न्यायपालिका के सदस्यों को शिक्षित करने, प्रशिक्षित करने और तैयार करने के लिए एक औपचारिक, संस्थागत व्यवस्था की सख्त जरूरत थी ताकि उन्हें आवश्यक ज्ञान और कौशल से लैस किया जा सके। यह भी आवश्यक समझा गया कि अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों में पहले दिन से ही नैतिक मूल्यों का समावेश हो। इस प्रकार, संस्थान का उद्देश्य जिला न्यायपालिका के सदस्यों को कानूनों के अद्यतन ज्ञान से लैस करना और उनमें एक अच्छे न्यायाधीश के गुणों को विकसित करना और विकसित करना है ताकि वे दिन-प्रतिदिन के न्यायिक कार्य की चुनौतियों का सामना कर सकें। यह महसूस किया गया कि इस तरह की कंडीशनिंग एक व्यक्तिगत न्यायाधीश के अंतर्निहित गुणों को अनुकूलित करेगी, ताकि वह न्याय वितरण प्रणाली में अपनी निर्दिष्ट भूमिका को प्रभावी ढंग से और कुशलता से निभाने की स्थिति में हो।

18. ग्राम पंचायत के सचिव ग्राम सभा की बैठकें बुलाते हैं। पंचायत की अध्यक्षता गांव के अध्यक्ष द्वारा की जाती है, जिसे सरपंच कहा जाता है।

19. बसंत प्रताप सिंह 01-01-2019 -३३.

20. हिदायतुल्लाह 25 फरवरी 1968 से 16 दिसंबर 1970 तक भारत के 11वें मुख्य न्यायाधीश और 31 अगस्त 1979 से 30 अगस्त 1984 तक भारत के छठे उपराष्ट्रपति रहे। वह 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे।

21. राज्य योजना बोर्ड का गठन सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प दिनांक 24.10 के माध्यम से किया गया था। 1972. मुख्यमंत्री राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं।

22. अटल गृह ज्योति योजना के लिए 2,581 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। अटल कृषि ज्योति योजना के लिए 4,592 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लिए 3,200 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

23. पांचवी पंचवर्षीय योजना।

24. 2021-22 के लिए राजकोषीय घाटा 50,598 करोड़ रुपये (जीएसडीपी का 4.47%) होने का अनुमान है। 2020-21 में, बजट स्तर पर अनुमानित जीएसडीपी के 4.96% की तुलना में संशोधित चरण में राजकोषीय घाटा जीएसडीपी के 5.66% तक बढ़ने का अनुमान है।

25. (c) Madhya Pradesh government announced the allocation of Rs 262 crores in the state budget.
26. (b) The scheme of the food parks aims at providing a mechanism to link agricultural production to the market by bringing together farmers, processors, and retailers. The Food Park Schemes is launched in 2008.
27. (b) Education: Madhya Pradesh has allocated 17% of its total expenditure for education in 2021-22. This is higher than the average allocation (15.8%) for education by all states (2020-21 BE).
28. (b) Madhya Pradesh is an agrarian state. Primary sector's contribution to the state's Gross Value Added (GVA) increased from 33.85% in 2011-12 to 46.98% in 2020-21.
29. (a) Security Paper Mill was established in 1968 at Hoshangabad, Madhya Pradesh. It produces papers for banknotes and non-judicial stamps.
30. (a) Madhya Pradesh has India's 1<sup>st</sup> green-field SEZ in Pithampur which covers total area of 1,114 Hectare and is located 35 km from the city of Indore.
31. (b) State hosts 7 food parks and 2 mega food parks.
32. (b) The Central Institute of Agricultural Engineering (CIAE), was established on Feb. 15, 1976.
33. (c) In Madhya Pradesh, the head office of Cotton Research Centre is located at Khargone.
34. (d) Total population of Madhya Pradesh as per 2011 census is 7.27 crore, of which male and female are 3.76 crore and 3.51 crore respectively. 51.8% , 48.2%

and constituting 15.54% and 21.04% of the total population respectively.

25. मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के बजट में 262 करोड़ रुपये के आवंटन की घोषणा की।
26. फूड पार्क की योजना का उद्देश्य किसानों, प्रसंस्करणकर्ताओं और खुदरा विक्रेताओं को एक साथ लाकर कृषि उत्पादन को बाजार से जोड़ने के लिए एक तंत्र प्रदान करना है। फूड पार्क योजना 2008 में शुरू की गई थी।
27. शिक्षा: मध्य प्रदेश ने 2021-22 में शिक्षा के लिए अपने कुल खर्च का 17% आवंटित किया है। यह सभी राज्यों (2020-21 बीई) द्वारा शिक्षा के लिए औसत आवंटन (15.8%) से अधिक है।
28. मध्य प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है। राज्य के सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 2011-12 में 33.85% से बढ़कर 2020-21 में 46.98% हो गया।
29. Security पेपर मिल की स्थापना 1968 में होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में हुई थी। यह बैंकनोटों और गैर-न्यायिक टिकटों के लिए कागजात तैयार करता है
30. मध्य प्रदेश में पीथमपुर में भारत का पहला ग्रीन-फील्ड एसईजेड है जो कुल 1,114 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करता है और इंदौर शहर से 35 किमी दूर स्थित है।
31. राज्य में 7 फूड पार्क और 2 मेगा फूड पार्क हैं।
32. सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग (सीएई) की स्थापना 15 फरवरी 1976 को हुई थी।
33. मध्य प्रदेश में कपास अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय खरगोन में स्थित है।
34. 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या 7.27 करोड़ है, जिसमें पुरुष और महिला क्रमशः 3.76 करोड़ और 3.51 करोड़ हैं। 51.8%, 48.2%

35. (a) The scheduled castes and the scheduled tribes constitute a significant portion of the population of the State 15.54% and 21.04%
36. (c) Dhar
37. (d) Madhya Pradesh audyogik vikas kendra nigam :  
To develop green field SEZs.  
To help in development of Industrial Development Centers.  
To acquire land for industries & also make all the necessary resources available.  
Promote Industrial development in state & in own jurisdiction. To explore and analyze possibilities of industrialization & also provide help in industry establishment.  
To develop Industrial projects either on our own or along with State Government, Municipal Corporations, any private company, association etc.  
To promote public units development & establishment.
38. (c) 'Farmers getting assistance under pm kisan samman nidhi are ineligible for the scheme' is incorrect.
39. (b) For the first time in Madhya Pradesh, the optical fiber factory is located in the Mandidweep district of Raisen. The optical fiber factory is built in collaboration with the country of Japan.
40. (a) 9 districts, The Madhya Pradesh Rural Livelihoods Project (MPRLP) works with local village assemblies, Gram Sabha, to facilitate and guide community-driven collective and individual action to reduce poverty in the state of Madhya Pradesh, India.
41. (b) 3rd September, 1948.
42. (c) 40 districts of Madhya Pradesh have population more than 10lakhs.
43. (b) 3 stages
44. (d) Dindori (1,004), Mandla (1,005) Alirajpur (1,009) Balaghat (1,021)
45. (c) District with highest population density – Bhopal (855 persons per sq. km.) The district with the lowest population density – Dindori (94 persons per sq. km.)

35. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति राज्य की जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और कुल जनसंख्या का क्रमशः 15.54% और 21.04% हैं।
36. धार
37. मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास केंद्र निगम :  
ग्रीन फील्ड एसईजेड विकसित करना।  
औद्योगिक विकास केन्द्रों के विकास में सहायता करना।  
उद्योगों के लिए भूमि अधिग्रहण करना और सभी आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराना।  
राज्य में और अपने अधिकार क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना। औद्योगिकीकरण की संभावनाओं का पता लगाना और उनका विश्लेषण करना और उद्योग स्थापना में भी सहायता प्रदान करना।  
औद्योगिक परियोजनाओं को या तो अपने दम पर या राज्य सरकार, नगर निगमों, किसी भी निजी कंपनी, संघ आदि के साथ विकसित करना।  
सार्वजनिक इकाइयों के विकास और स्थापना को बढ़ावा देना।
38. 'पीएम किसान सम्मान निधि के तहत सहायता प्राप्त करने वाले किसान योजना के लिए अपात्र हैं' गलत है।
39. मध्यप्रदेश में पहली बार ऑप्टिकल फाइबर फैक्ट्री भोपाल के मंडीद्वीप जिले में स्थित है। ऑप्टिकल फाइबर फैक्ट्री जापान देश के सहयोग से बनाई गई है।
40. 9 जिले, मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका परियोजना (एमपीआरएलपी) भारत के मध्य प्रदेश राज्य में गरीबी को कम करने के लिए समुदाय संचालित सामूहिक और व्यक्तिगत कार्रवाई को सुविधाजनक बनाने और मार्गदर्शन करने के लिए स्थानीय ग्राम सभाओं, ग्राम सभा के साथ काम करती है।
41. 3 सितंबर, 1948।
42. मध्य प्रदेश के 40 जिलों की जनसंख्या 10 लाख से अधिक है।
43. 3 चरण
44. डिंडोरी (1,004), मंडला (1,005) अलीराजपुर (1,009) बालाघाट (1,021)
45. सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला – भोपाल (855 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी.)

- 46.(b) Anuppur, Betul, Chindwada
- 47.(c) 28<sup>th</sup> Madhya Pradesh's literacy rate has witnessed aloft tendency and it was 69.32 % as per Census 2011.
- 48.(d) 8<sup>th</sup>
- 49.(b) There are 15.62% Scheduled Caste (SC) and 21.09% Scheduled Tribe (ST) of total population in Madhya Pradesh. i.e. 36.71%
- 50.(c) .
- 51.(c) Burhanpur is the district where MP's first thermal power station installed.
- 52.(d) Rs. 1402. 22 crores
- 53.(b) State energy development Corporation established by the Government of Madhya Pradesh in 1982 as the nodal agency for implementing various programs and policies of the GoI.
- 54.(a) Bhopal
- 55.(c) There was an agreement in 1973 between the State Governments of Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Bihar for the construction of the dam, in which the states shared the expenditure in the ratio of 2:1:1.
- 56.(b) Madhya Pradesh and Rajasthan.
- 57.(c) 1992
- 58.(a) July 10, 2012
- 59.(c) The current source of gas is Coal Bed Methane (CBM) blocks in Sohagpur East (SP-E) and Sohagpur West (SP-W) located in Shahdol district in Madhya Pradesh of RIL.
- 60.(d) Oil India said the project is split between a 16 MW capacity plant at Patan in Gujarat and a 38 MW at Chandgarh in Madhya Pradesh.
- 61.(a) Bhilai Steel Plant is India's sole producer and supplier of world-class Indian Railways. Bhilai Steel Plant located in Bhilai is in the Indian state of Chhattisgarh. It was set up in 1955 with the help of the USSR (Russia).

46. अनूपपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा
47. 28 वें मध्य प्रदेश की साक्षरता दर में उच्च प्रवृत्ति देखी गई है और यह 2011 की जनगणना के अनुसार 69.32% थी।
48. 8वां
49. मध्य प्रदेश में कुल जनसंख्या का 15.62% अनुसूचित जाति (एससी) और 21.09% अनुसूचित जनजाति (एसटी) है। यानी 36.71%
50. (c)
51. बुरहानपुर वह जिला है जहां एमपी का पहला थर्मल पावर स्टेशन स्थापित है।
52. रु. 1402. 22 करोड़
53. मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 1982 में भारत सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों और नीतियों को लागू करने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में स्थापित निगम।
54. भोपाल
55. बांध के निर्माण के लिए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की राज्य सरकारों के बीच 1973 में एक समझौता हुआ था, जिसमें राज्यों ने 2:1:1 के अनुपात में खर्च साझा किया था।
56. मध्य प्रदेश और राजस्थान।
57. 1992
58. 10 जुलाई 2012
59. गैस का वर्तमान स्रोत आरआईएल के मध्य प्रदेश में शहडोल जिले में स्थित सोहागपुर पूर्व (एसपी-ई) और सोहागपुर पश्चिम (एसपी-डब्ल्यू) में कोल बेड मीथेन (सीबीएम) ब्लॉक हैं।
60. ऑयल इंडिया ने कहा कि यह परियोजना गुजरात के पाटन में 16 मेगावाट क्षमता के संयंत्र और मध्य प्रदेश के चांदगढ़ में 38 मेगावाट क्षमता के संयंत्र के बीच विभाजित है।
61. भिलाई स्टील प्लांट भारत का एकमात्र उत्पादक और विश्व स्तरीय भारतीय रेलवे का आपूर्तिकर्ता है। भिलाई में स्थित भिलाई इस्पात संयंत्र भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में है। इसकी स्थापना 1955 में नै (रूस) की मदद से की गई थी।

- 62.(c) Research in agriculture technology
- 63.(c) Hindustan Coca-Cola Beverages Ltd (HCCBL) is planning to build a bottling plant in Hoshangabad, Madhya Pradesh, India.
- 64.(c) Sagar Bina refinery is located at Bina in the Sagar district of the state of Madhya Pradesh in India.
- 65.(c) India's Punj Lyod and Israel Weapon Industry under the Make in India Programme. The joint venture company, Punj Lloyd Raksha Systems, will help the armed forces in replacing their weapons with sophisticated and high precision products.
- 66.(c) 1965
- 67.(b) Sehore.
- 68.(d) Established in hoshangabad district of Madhya Pradesh.
- 69.(a) Satna
- 70.(c) Federation of Madhya Pradesh Chamber of Commerce & Industry (FMPCCI) was established in the year 1975 with a view to facilitate the Trade
- 71.(b) Barlai Sugar Mill in Indore is the biggest sugar mill in Madhya Pradesh. Bhopal Sugar Mill is situated in Sehore District. It was established in 1939.
- 72.(b) 8, balaghat 'chinnor rice' is the latest.
- 73.(a) 1984
- 74.(b) SH-19[A]
- 75.(a) January 1, 2014
- 76.(a) On June 23<sup>rd</sup>, 2018, Prime Minister Narendra Modi launched 'Sutra Seva-Madhya Pradesh ki Apni Bus' in a program
- 77.(c) It comes under Western Railways zone of Indian Railways. Four major Railway Tracks pass through Ratlam City, these are towards Mumbai, Delhi, Ajmer and Khandwa.
- 78.(d) 2018
- 79.(a) October 31, 1988.
- 80.(b) Women

62. कृषि प्रौद्योगिकी में अनुसंधान
63. हिंदुस्तान कोका-कोला बेवरेजेज लिमिटेड (एचसीसीबीएल) भारत के मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में एक बॉटलिंग प्लांट बनाने की योजना बना रहा है।
64. सागर बीना रिफाइनरी भारत में मध्य प्रदेश राज्य के सागर जिले के बीना में स्थित है।
65. मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत भारत का पुंज ल्योद और इजराइल हथियार उद्योग। संयुक्त उद्यम कंपनी, पुंज लॉयड रक्षा सिस्टम, सशस्त्र बलों को अपने हथियारों को परिष्कृत और उच्च परिशुद्धता उत्पादों के साथ बदलने में मदद करेगी।
66. 1965
67. सीहोर।
68. मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थापित।
69. सतना
70. फेडरेशन ऑफ मध्य प्रदेश चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एचडब्ल्यू) की स्थापना वर्ष 1975 में व्यापार की सुविधा के लिए की गई थी।
71. इंदौर की बरलाई चीनी मिल मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी चीनी मिल है। भोपाल चीनी मिल सीहोर जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1939 में हुई थी।
72. 8, बालाघाट 'चिन्नौर चावल' नवीनतम है।
73. 1984
74. एसएच -19 (ए)
75. 1 जनवरी 2014
76. 23 जून, 2018 को, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कार्यक्रम में 'सूत्र सेवा-मध्य प्रदेश की अपनी बस' का शुभारंभ किया।
77. यह भारतीय रेलवे के पश्चिमी रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आता है। चार प्रमुख रेलवे ट्रैक रतलाम शहर से होकर गुजरते हैं, ये मुंबई, दिल्ली, अजमेर और खंडवा की ओर हैं।
78. 2018
79. 31 अक्टूबर, 1988।
80. महिला



81. (a) The 2019 Indian general election were held in Madhya Pradesh in 4 phases- between 29 April and 19 May 2019 to constitute the 17th Lok Sabha.
82. (b) 71.10 %
83. (d) The Constitution does not fix the term of Advocate General in India. He remains in the office during the pleasure of the Governor. The Constitution does not contain the procedure and grounds to remove the Advocate General of State. Governor can remove him/her at any point in time.
84. (c) M.P. Wakf Board has been constituted under the provision of Wakf Act, 1954. The Union Govt. has constituted a new Act in 1995.
85. (a) The Madhya Pradesh Minorities Commission (Procedure) Regulations, 1996. (ii) These regulations will come into force with effect from the 31st day of March, 1997. (a) "Act" means the Madhya Pradesh Rajya Alpsankhyak Ayoga Adhiniyam., 1996.
86. (d) 9.53%
87. (b) 18 November 1946 Kanpur, United Provinces, British India (now in Uttar Pradesh, India).
88. (b) Sushma Swaraj.
89. (d) All of these.
90. (d) Kshama yachna and kaurav kaunpandav kaun both poems are the work of great Atal Bihari Bajpayee.
91. (a) Head
92. (d) Pig/Boar
93. (a) Baiga
94. (a) Service Marriage
95. (b) Narmada Singh Gond
96. (a) Kol
97. (c) 1/5
98. (d) All of these
99. (c) Deori
100. (c) Jhabua

81. 2019 का भारतीय आम चुनाव मध्य प्रदेश में 4 चरणों में हुआ— 29 अप्रैल और 19 मई 2019 के बीच 17वीं लोकसभा का गठन किया गया।

82. 71.10%

83. संविधान भारत में महाधिवक्ता का कार्यकाल निर्धारित नहीं करता है। वह राज्यपाल के प्रसादपर्यन्त अपने पद पर बना रहता है। संविधान में राज्य के महाधिवक्ता को हटाने की प्रक्रिया और आधार शामिल नहीं हैं। राज्यपाल उन्हें किसी भी समय हटा सकते हैं।

84. म.प्र. वक्फ बोर्ड का गठन वक्फ अधिनियम, 1954 के प्रावधान के तहत किया गया है। केंद्र सरकार। 1995 में एक नए अधिनियम का गठन किया है।

85. मध्य प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग (प्रक्रिया) विनियम, 1996। (पप) ये नियम 31 मार्च, 1997 से लागू होंगे। (ए) :अधिनियम: का अर्थ मध्य प्रदेश राज्य अल्पसंख्याक आयोग अधिनियम है। 1996.

86. 9.53%

87. 18 नवंबर 1946 कानपुर, संयुक्त प्रांत, ब्रिटिश भारत (अब उत्तर प्रदेश, भारत में)।

88. सुषमा स्वराज।

89. ये सभी।

90. क्षमा यज्ञ और कौरव कौन—पांडव कौन दोनों कविताएं महान अटल बिहारी बाजपेयी की कृति हैं।

91. सिर

92. सुअर/सूअर

93. बैगा

94. सेवा विवाह

95. नर्मदा सिंह गोंडी

96. कोलो

97. 1/5

98. ये सभी

99. देवरिया

100. झाबुआ